



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31—अप्रैल 6, 2012 (चैत्र 11, 1934)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31—APRIL 6, 2012 (CHAITRA 11, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	175	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	321	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	423	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 611
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 4775
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 219
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	175	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	321	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	423	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	611
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4775
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	219
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the -Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2012

संकल्प

सं. 5(1)-बी(पी.डी.)/2011--आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2011-2012 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 8% (आठ प्रतिशत) 01.04.2011 से 30.11.2011 तक की अवधि के लिए तथा 01.12.2011 से 8.6% (आठ दसमलव छः प्रतिशत) रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :--

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ब्रजेन्द्र नवनीत
उप-सचिव (बजट)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2012

सं. 5/4/2011-चमड़ा--केन्द्र सरकार ने 11वीं योजना की बची हुई अवधि और 12वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के तहत 600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपये) के आवंटन के साथ "मेगा लेदर क्लस्टर" नामक उप-योजना को अनुमोदित कर दिया है। मेगा लेदर क्लस्टर (एमएलसी) उप-योजना

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के अंतर्गत पूर्ववर्ती योजना "लेदर पार्क" का स्थान लेगी।

2. यह योजना उच्च वृद्धि संभावना वाले उन औद्योगिक क्लस्टरों/अवस्थानों पर ध्यान देती है, जहां विश्व स्तरीय अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराकर रणनीतिक हस्तक्षेप किए जाने अपेक्षित हैं। परियोजना लागत में मुख्य अवसंरचना, विशेष अवसंरचना, उत्पादन अवसंरचना, मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और निर्यात सेवाओं से संबंधित अवसंरचना जैसे विभिन्न अवसंरचना विकास शामिल होंगे।

3. भारत सरकार 125 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर की अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन, भूमि की लागत को छोड़कर, परियोजना के सभी संघटकों के लिए परियोजना लागत का 70 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएगी। क्लस्टर में कम से कम 40 एकड़ भूमि होनी चाहिए। सरकारी अनुदान की क्रमिक संरचना क्लस्टर में भूमि के क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी, जो निम्नानुसार है :--

- (क) 40--60 एकड़ भूमि का एमएलसी-भारत सरकार की सहायता 50 करोड़ रुपये तक सीमित है।
- (ख) 61--100 एकड़ भूमि का एमएलसी-भारत सरकार की सहायता 70 करोड़ रुपये तक सीमित है।
- (ग) 101--150 एकड़ भूमि का एमएलसी-भारत सरकार की सहायता 105 करोड़ रुपये तक सीमित है।
- (घ) 151 एकड़ से अधिक भूमि का एमएलसी-भारत सरकार की सहायता 125 करोड़ रुपये तक सीमित है।

4. पार्कों के विकास और प्रबंधन के लिए उद्यमियों द्वारा विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की स्थापना करनी होगी। भारत सरकार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले एसपीवी द्वारा प्रस्तुत परियोजना को अनुमोदन देगी। एसपीवी को परियोजना का 30 प्रतिशत नकद अंशदान के रूप में लाना होगा, भूमि की लागत उसे स्वयं वहन करनी होगी, एसपीवी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होगी, जिसका गठन अंशधारकों, विशेषरूप से चमड़ा क्षेत्र में कार्य कर रहे इच्छुक उद्यमियों के समूह (कानूनी रूप से स्वतंत्र न्यूनतम 7 कंपनियों) द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक उद्यमी या कानूनी रूप से स्वतंत्र इकाइयों की शुद्ध मालियत कम-से-कम 1 करोड़ रुपये तथा एसपीवी का गठन करने वाले सात प्रवर्तकों की शुद्ध मालियत संयुक्त रूप से कम-से-कम 10 करोड़ रुपये होनी चाहिए। स्वामित्व की व्यापकता सुनिश्चित करने और प्रभुत्व को रोकने के लिए किसी

व्यक्ति/कंपनियों के समूह का हिस्सा एसपीवी की इक्विटी का 25 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

5. सरकार परियोजना शुरू करने के लिए डीपीआर के अनुमोदन चरण से ही, पीएमसी के तौर पर ऐसी पेशेवर एजेंसी की सेवाएं लेगी जिसे योजना के कार्यान्वयन में औद्योगिक क्लस्टर अवसंरचना विकसित करने, वित्तीय मूल्य निरूपण करने और क्रियान्वयन का अनुभव प्राप्त होगा।

6. यह उप-योजना समूचे भारत पर लागू है। योजना के दिशानिर्देश विभाग की वेबसाइट (www.dipp.nic.in) पर उपलब्ध हैं। इच्छुक चमड़ा उद्यमी योजना के तहत प्रारंभिक प्रस्ताव दिशानिर्देशों में बताए अनुसार सीधे विभाग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।

गुरप्रीत गढोक
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2012

सं. एफ-7-8/2009-(एमसी)--राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था
आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3(2) के अनुसरण

में केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री जफर आगा, सी-27, प्रैस एन्क्लेव, साकेत दिल्ली को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के अंतर्गत सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (एनसीएमईआई) का सदस्य नियुक्त करती है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के सदस्य के रूप में उपर्युक्त व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि सदस्य के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की होगी और उनका वेतन तथा भत्ते राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 24(2)(क) के अधीन अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन तथा भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों, नियमों के अनुसार विनियमित होंगे।

उपर्युक्त सदस्य के कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति श्री जफर आगा को भेजी जाए।

अमित खरे
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 19th March 2012

RESOLUTION

No. 5(1)-B(PD)/2011—It is announced for general information that during the year 2011-2012, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 8% (Eight per cent) for the period from 01.04.2011 to 30.11.2011 and 8.6% (eight point six per cent) with effect from 01.12.2011. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be Published in Gazette of India.

BRAJENDRA NAVNIT
Dy. Secy. (Budget)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 20th March 2012

No. 5/4/2011-Leather—The Central Government has approved a sub-scheme titled "Mega Leather Cluster" with an allocation of Rs. 600 crore (Rupees six hundred crore) under Indian Leather Development Programme (ILDIP) for Implementation during the remaining period of 11th Plan and 12th Plan period. The Mega Leather Cluster (MLC) sub-scheme will replace the erstwhile scheme of "Leather Parks" under Indian Leather Development Programme (ILDIP).

2. The Scheme targets industrial clusters/locations with high growth potential, which require strategic interventions by way of providing world-class infrastructure support. The project cost will cover various infrastructure developments like Core Infrastructure, Special Infrastructure, Production Infrastructure, HRD & Social Infrastructure, R&D Infrastructure & Export Services related infrastructure.

3. The Government of India would provide assistance limited to 70% of the project cost as grant in aid for all components of

the project, except the cost of the land, subject to a maximum ceiling of Rs. 125 crore per cluster. The cluster should have a minimum area of 40 acres of land. The graded structure of Government grant would be provided depending on the area of land in the cluster which is as under :—

- (a) MLC of 40—60 acres land—GoI Assistance limited to Rs. 50 crore;
- (b) MLC of 61—100 acres land—GoI assistance limited to Rs. 70 crore;
- (c) MLC of 101—150 acres land—GoI assistance limited to Rs. 105 crore;
- (d) MLC of more than 151 acres land—GoI assistance limited to Rs. 125 crore.

4. A Special Purpose Vehicle (SPV) will have to be set up by entrepreneurs for development and management of park. The Government of India would approve the project submitted by SPV who would be the recipient of the assistance under the scheme. The SPV would have to bring in 30% of the project as cash contribution apart from the land itself at its own cost. The SPV will be a company registered under the Companies Act, 1956 formed by the stakeholders, particularly a group of willing entrepreneurs (minimum being 7 legally independent companies) that are engaged in the leather sector. The net worth of each of the entrepreneurs or legally independent units has to be at least Rs. 1 crore and the combined net worth of the seven promoters forming the SPV should be at least Rs. 10 crore. The share of any individual/group of entities shall be less than 25% of equity of SPV to ensure widely spread ownership and to preclude domination.

5. The Government will engage the services of a professional agency as PMC, which has proven experience in developing, financing appraising and executing industrial cluster infrastructure in the implementation of the scheme, right from the stage of approval of DPR to commissioning of the project.

6. The sub-scheme is applicable all over India. The guidelines of the scheme are available on the website of the Department (www.dipp.nic.in). Interested leather entrepreneurs can submit preliminary proposal under the scheme as detailed in the guidelines directly to the Department for approval.

GURPREET GADHOK
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 7th March 2012

No. F. 7-8/2009-(MC)—In pursuance of the Section 3(2) read with Section 5 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004, the Central Government is hereby pleased to appoint Shri Zafar Agha, C-27, Press Enclave, Saket, Delhi, as Member of National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) to discharge the functions

of a Member under the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004.

2. The tenure of the appointment of the aforesaid person as member, NCMEI shall be for five years with effect from the date he assumes office as such Member, and his salary and allowances shall be regulated in accordance with the 'Salaries and Allowances and other conditions of service of Chairperson and other members, Rules' under Section 24(2) (a) of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004.

3. The Headquarters of the office of the aforesaid Member shall be in New Delhi.

ORDER

Ordered, that notification be published in the Gazette of India for general information.

Ordred also, that a copy of the notification be communicated to Shri Zafar Agha.

AMIT KHARE
Jt. Secy.